



हुडको पर अक्सर पूछे जाने वाले

प्रश्न 1. हुडको क्या है?

उत्तर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) एक नवरत्न सीपीएसई, 1970 में अपनी स्थापना के बाद से भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। "सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता" के आदर्श वाक्य के साथ काम करते हुए, हुडको सामाजिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय व्यवहार्यता को जोड़ता है, जो वंचित वर्गों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले समूहों (एलआईजी) की आवास आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एन. बी. एफ. सी.-आई. एफ. सी.) के रूप में अपने पदनाम के साथ, हुडको एक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण में योगदान देते हुए स्थायी परिसंपत्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

प्र. 2. हुडको कितने स्थानों या शाखाओं पर काम करता है?

उत्तर। हुडको नई दिल्ली में स्थित अपने पंजीकृत और निगमित कार्यालय के साथ पूरे भारत में 20 क्षेत्रीय कार्यालयों और 11 विकास कार्यालयों का संचालन करता है।

प्र. 3. हुडको के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर। कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: शहरी विकास पर विशेष जोर देते हुए आवास और अवसंरचना क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों को वित्त/ऋण सुविधा प्रदान करना. भारत और विदेशों में नए/उपग्रह शहरों की स्थापना सहित आवास और अवसंरचना क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के विकास के लिए वित्त या उपक्रम या सहयोग करना. आवास और अवसंरचना क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के वित्तपोषण के उद्देश्य से जारी किए गए डिबेंचरों और बांडों की सदस्यता लेना. निर्माण सामग्री के औद्योगिक उद्यमों की स्थापना के लिए वित्त या उपक्रम करना भारत सरकार और अन्य स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त धन को अनुदान के रूप में या अन्यथा देश में आवास और अवसंरचना क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों को दिशा देने या वित्तपोषित करने या उनके विकास में सहायता करने के उद्देश्यों के लिए प्रशासित करना। भारत और विदेशों में आवास और अवसंरचना क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों से संबंधित परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देना, स्थापित करना, सहायता करना, सहयोग करना और प्रदान करना। वैकल्पिक निवेश कोष (ए. आई. एफ.), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आर. ई. आई. टी.) और/या अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (आई. एन. वी. आई. टी.) के वैकल्पिक निवेश कोष (ए. आई. एफ.), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आर. ई. आई. टी.) और/या अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (आई. एन. वी. आई. टी.) में निवेश करना और/या सदस्यता लेना।

प्र. 4. इसका मिशन क्या है?

उत्तर। जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्थायी आवास विकास को बढ़ावा देना।

प्र. 5. इसका विज़न क्या है?

उत्तर। लोगों के जीवन को बदलने के लिए स्थायी आवास विकास को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख तकनीकी-वित्तीय संस्थान बनना।

प्र. 6. क्या हडको एक आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) है और यदि ऐसा है, तो हडको का नियामक कौन है?

उत्तर। हां, हडको को तत्कालीन नियामक एनएचबी के साथ एचएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया था। वित्त अधिनियम 2019 के अनुसार इस प्रकार एच. एफ. सी. को संचालित करने की शक्ति एन. एच. बी. से आर. बी. आई. को हस्तांतरित की गई। आर. बी. आई. ने 22.10.2020 पर एच. एफ. सी. की नई नियामक रूपरेखा जारी की। एन. बी. एफ. सी. के लिए आर. बी. आई. के संशोधित नियामक ढांचे में हाल के परिवर्तनों के कारण हडको पर लागू मौजूदा और संशोधित नियामक ढांचे की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। हडको के मौजूदा व्यापार मॉडल और भविष्य की विकास संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हडको द्वारा गठित टियर-1 समिति ने हडको को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत करने की सिफारिश की है। वही प्रक्रिया में है।

प्र. 7. क्या हडको आई. एस. ओ. प्रमाणित संस्थान है?

उत्तर। हां, हडको आईएसओ 9001 है: 2015 गुणवत्ता प्रबंधन के लिए प्रमाणित संस्थान, अपनी गतिविधियों की पूरी श्रृंखला के लिए जिसमें परियोजना और खुदरा वित्तपोषण सेवाएं, वित्त पोषण के लिए संसाधन जुटाना, परामर्श और संयुक्त उद्यम और मानव निपटान योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेटवर्किंग शामिल हैं।

प्र. 8. कंपनी के रूप में हडको की स्थिति क्या है?

उत्तर। वर्तमान में हडको एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) है।

प्र. 9. क्या हडको की अपनी प्रशिक्षण शाखा या प्रभाग भी है? इसके उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर। हां. हडको की अपनी नई दिल्ली में स्थित मानव निपटान प्रबंधन संस्थान (एच. एस. एम. आई.) नामक एक समर्पित अनुसंधान और प्रशिक्षण शाखा है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

मानव निपटान योजना और प्रबंधन में जागरूकता, अभिविन्यास और कौशल को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाना. मूल्यांकन अध्ययन, कार्रवाई और नीति अनुसंधान, प्रलेखन और प्रसार करना. राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करके एक थिंक टैंक और परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ नेटवर्किंग को बढ़ावा देना.

उत्कृष्टता के मुख्य क्षेत्रों में एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र की स्थापना करना. अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से अपने संचालन की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए हडको के कार्यकर्ताओं की क्षमता को बढ़ाना।

प्र. 10. हडको कर्मचारियों की संरचना क्या है?

उत्तर। हडको कर्मचारियों की संरचना इस प्रकार है:

स्तर	मौजूदा (₹ में)	संशोधित (₹ में)
CMD	80,000- 1,25,000	2,00,000 – 3,70,000
Director	75,000 – 1,00,000	1,80,000 – 3,40,000
Sr. Executive Director (E9)	62,000 – 80,000	1,50,000 – 3,00,000
Executive Director (E-8)	51,300 – 73,000	1,20,000 – 2,80,000
General Manager (E-7)	43,200 – 66,000	1,00,000 – 2,60,000
Jt. General Manager (E-6)	36,600 – 62,000	90,000 – 2,40,000
Dy. General Manager (E-5)	32,900 – 58,500	80,000 – 2,20,000
Asst. General Manager (E-4)	29,100 – 54,500	70,000 – 2,00,000
Sr. Manager (E-3)	24,900 – 50,500	60,000 – 1,80,000
Manager (E-2)	20,600 – 46,500	50,000 – 1,60,000
Dy. Manager (E-1)	16,400 – 40,500	40,000 – 1,40,000
Asst. Manager (E-0)	12,600 – 32,500	30,000 – 1,20,000
Asst. Grade Gr – I (NE-5)	10600 - 28200	26000-87000
Asst. Grade Gr – II (NE-4)	9800-26000	24000-80000
Asst. Grade Gr – III (NE-3)	9200-24500	22000-75000
Attendant Farash (SG) (NE-2)	8600-22900	21000-70000
Attendant Farash (NE-1)	9200-21800	19500-65000

प्र. 11. हडको कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?

उत्तर। हडको कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

प्र. 12. हडको का संसाधन आधार क्या है?

उत्तर। हडको की स्थापना रुपये के इक्विटी आधार के साथ की गई थी। 2 करोड़। वर्षों से, सरकार द्वारा इक्विटी आधार का विस्तार किया गया है। हडको का वर्तमान अधिकृत पूंजी आधार रु। 2500 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी रु। 2001.90 करोड़। नवीनतम अपडेट के लिए कृपया हडको वेबसाइट www.hudco.org.in देखें।

प्रश्न 13. हडको के कार्यक्रम क्या हैं?

उत्तर। हडको शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को लाभान्वित करने के लिए नीचे सूचीबद्ध कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला के तहत सहायता प्रदान करता है:

आवास वित्त: देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक आवास-ई. डब्ल्यू. एस. और एल. आई. जी.-एम. आई. जी. और एच. आई. जी. के लिए आवास-सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए किराये का आवास। और सार्वजनिक अभिकरणों द्वारा आवास अभिकरणों के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की अभिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण व्यक्तिगत आवास ऋण शहरी निवेश वित्त: जल आपूर्ति, मलजल निकासी, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य शहर-स्तरीय उपयोगिता अवसंरचना सड़क और परिवहन (फ्लाईओवर, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बस टर्मिनल, पार्किंग परिसर और एक्सप्रेसवे) सामाजिक अवसंरचना-स्कूल, अस्पताल, खेल परिसर, वाणिज्यिक परिसर, मल्टीप्लेक्स आदि। उभरता हुआ क्षेत्र-आईटी पार्क, एक्सप्रेसवे, बिजली, दूरसंचार आदि। परामर्श सेवाएँ: वास्तुकला शहरी डिजाइन परिदृश्य शहरी और क्षेत्रीय योजना आंतरिक डिजाइन प्रशिक्षण: अपनी प्रशिक्षण और अनुसंधान शाखा-मानव बस्तियाँ और प्रबंधन संस्थान के माध्यम से आवास और शहरी विकास क्षेत्र में पेशेवरों की क्षमता निर्माण अनुसंधान अनुदान के माध्यम से शहरी क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन करता है। गृह कर्मचारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम, एच. एस. एम. आई., आई. आई. एम., एन. आई. बी. एम. आदि में प्रशिक्षण।

प्र. 14. हडको ऋण सहायता के लिए पात्र उधारकर्ता कौन हैं?

उत्तर। पात्र उधारकर्ता हैं:

1. राज्य स्तरीय वित्तपोषण संस्थान/निगम 2. जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड 3. विकास प्राधिकरण 4. आवास और शहरी विकास के लिए राज्य कार्यात्मक उधारकर्ता 5. नए नगर विकास उधारकर्ता 6. क्षेत्रीय योजना बोर्ड 7. सुधार न्यास 8. नगर निगम/परिषद 9. संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ 10. सहकारी समितियाँ/न्यास 11. गैर सरकारी संगठन 12. बी. ओ. टी. प्रचालक, रियायत पाने वालों सहित निजी कंपनियाँ/उधारकर्ता

प्र. 15. आवास वित्त के तहत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियाँ क्या हैं?

उत्तर। सभी प्रकार की आवास परियोजनाओं में शामिल हैं:

1. ग्रामीण आवास 2. शहरी आवास 3. सहकारी आवास 4. सामुदायिक शौचालय 5. स्लम उन्नयन 6. पुलिस आवास सहित कर्मचारी आवास 7. 8. मरम्मत और नवीनीकरण। गैर सरकारी संगठनों द्वारा आवास 9. निजी क्षेत्र आवास 10. टेकआउट वित्त 11. भूमि अधिग्रहण निर्माण योजनाएं रियल एस्टेट जैसे मॉल, बाजार परिसर, कार्यालय परिसर, आई. टी. पार्क, होटल, रिसॉर्ट्स, मनोरंजन, एस. ई. जेड., स्पा, स्वास्थ्य क्लब, कल्याण केंद्र।

प्र. 16. बुनियादी ढांचा क्षेत्र में हडको वित्तपोषण के लिए किस प्रकार की परियोजनाएं पात्र हैं?

उत्तर। निम्नलिखित का निर्माण, संवर्धन और सुधार: 1. जल आपूर्ति परियोजनाएँ 2. मलजल निकासी और जल निकासी 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 4. कम लागत वाला स्वच्छता 5. एकीकृत क्षेत्र विकास योजनाएं 6. सामाजिक अवसंरचना 7. परिवहन-सड़कें, पुल, बस अड्डे, बंदरगाह, हवाई अड्डे आदि। 8. वाणिज्यिक/आर्थिक अवसंरचना 9. बिजली-उत्पादन, पारेषण और वितरण 10. औद्योगिक और व्यावसायिक अवसंरचना-एस. ई. जेड., गोदाम आदि। 11. सूचना/संचार/मनोरंजन (आईसीई) 12. दूरसंचार 13. पारिस्थितिकीय रूप से उपयुक्त अवसंरचना परियोजनाएं।

प्र. 17. हडको से परियोजना ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर। उधारकर्ता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में ऋण आवेदन निकटतम हडको कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। निर्धारित आवेदन पत्र हडको वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है: www.hudco.org.in

प्र. 18. हडको की ब्याज दर क्या है?

उत्तर। हडको की ब्याज दर परियोजनाओं के प्रकार, उधारकर्ता की श्रेणी, उधारकर्ता की रेटिंग पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हडको की वेबसाइट www.hudco.org.in देखें।

प्रश्न 19. उधारकर्ता हडको को ऋण के लिए आवेदन करने के लिए अपना प्रस्ताव कहाँ जमा कर सकता है?

उत्तर। सभी योजना प्रस्तावों को आम तौर पर परियोजना के भौगोलिक क्षेत्राधिकार वाले हडको के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकार किया जाता है। हालांकि, उधारकर्ता के विशिष्ट अनुरोध पर, प्रस्ताव को किसी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है।

प्र. 20. हडको से ऋण के लिए आवेदन करते समय सबसे पहले किससे संपर्क किया जाता है?

उत्तर। ऋण आवेदन को स्वीकार करने और पंजीकृत करने के लिए, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक ग्राहक संबंध अधिकारी (सी. आर. ओ.) उपलब्ध है। सी. आर. ओ. हडको के निर्धारित दिशानिर्देशों के भीतर सभी परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने और पात्रता निर्धारित करने और योजनाओं के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के पूर्ण सेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

प्र. 21. हडको द्वारा कौन सी परामर्श सेवाएँ प्रदान की जाती हैं?

उत्तर। हडको ने डिजाइन और परामर्श सेवाओं में प्रवीणता विकसित की है और निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं: आर्किटेक्चरल डिजाइन और विस्तृत कार्य रेखाचित्र, संरचनात्मक डिजाइन, परियोजना अनुमान, आंतरिक और बाहरी सेवाओं का डिजाइन, परिदृश्य योजना और डिजाइन, आवास, शहरी और क्षेत्रीय योजना मुद्दों

के लिए परियोजना रिपोर्ट और व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करना। अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं; शहर विकास योजनाओं (सीडीपी), मास्टर प्लान आदि की तैयारी।

प्र. 22. हडको के संबंध में अगस्त क्रांति भवन का क्या महत्व है?

उत्तर। अगस्त क्रांति भवन एक विशिष्ट और बहु उपयोगकर्ता आधुनिक वाणिज्यिक परिसर है जिसे हडको द्वारा प्लॉट नंबर 25, भीकाजी गामा प्लेस, नई दिल्ली में विकसित किया गया है। भीकाजी गामा वाणिज्यिक परिसर और अफ्रीका एवेन्यू से घिरा हुआ, यह दिल्ली के विभिन्न स्थानों से प्रमुख रूप से सुलभ है। ई. पी. एफ. ओ., एल., गेल इंडिया लिमिटेड, आयकर कार्यालय, महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आदि जैसे कार्यालय और ऐसे कई प्रतिष्ठित संस्थान आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा, यह अन्य उच्च श्रेणी की सेवाओं और सुविधाओं जैसे 5-सितारा होटलों जैसे हयात रीजेंसी दिल्ली, ऑल एमएस, सफदरजंग अस्पताल जैसे अस्पतालों के निकट है। अगस्त क्रांति भवन के परिसर में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कार्यालय हैं।

प्र. 23. हडको आर्ट गैलरी का उद्देश्य क्या है?

उत्तर। हडको आर्ट गैलरी अगस्त क्रांति भवन का एक अभिन्न अंग है जिसमें 900 वर्ग फुट कालीन क्षेत्र और 85 फुट लंबी दीवार है। इसमें लगभग 400 वर्ग फुट का एक खुला क्षेत्र है जो केंद्रीय भूदृश्य आलिंद में बहता है जो आगंतुकों को इकट्ठा करने और बातचीत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका उद्देश्य कला से संबंधित प्रदर्शनियों का समर्थन करके लोगों की सेवा करना है। यह केवल काम पर रखने के लिए उपलब्ध स्थान नहीं है, यह कला को बढ़ावा देने और स्थापित और उभरते कलाकारों के कार्यों को प्रदर्शित करने का मंच है।

प्र. 24. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हडको द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर। हडको ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी तकनीकी सहायता प्रदान की थी। घरों के निर्माण और संबंधित मामलों पर क्या करें और क्या न करें पर पर्चे और किताबें वितरित की गई थीं। मॉडल विलेज और मॉडल बस्ती जैसी प्रदर्शन परियोजनाओं का निर्माण मॉडल विलेज और मॉडल बस्ती योजनाओं के हिस्से के रूप में हडको द्वारा निष्पादित किया गया था।

प्र. 25. क्या हडको की वित्तीय सहायता भारत सरकार की कार्य योजना योजनाओं के लिए उपलब्ध है?

उत्तर। हां, संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त के लिए राज्य सरकार के हिस्से/यू. एल. बी. के हिस्से पर विचार किया जा सकता है।

प्र. 26. क्या हडको सार्वजनिक जमा स्वीकार करता है?

उत्तर। नहीं, हडको ने जमा की स्वीकृति/नवीनीकरण को बंद कर दिया था। 01.07.2019

प्र. 27. शहरी/ग्रामीण आवास के लिए लागत प्रभावी निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए हड़को क्या कर रहा है?

उत्तर। हड़को भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक योजना, भवन केंद्रों के राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से जमीनी स्तर पर आवास और अवसंरचना क्षेत्र में उपयोग के लिए उपयुक्त, लागत प्रभावी, निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में योगदान देता है। भवन केंद्र सी. बी. आर. आई. जैसे राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान विकास निकायों द्वारा लाए गए अभिनव, लागत प्रभावी, टिकाऊ और सौंदर्य संचालन को बढ़ावा देते हैं। एस. ई. आर. सी., एन. ई. ई. आर. आई., आर. आर. एल., ए. एस. टी. आर. ए., सी. एस. आर., डी. ए., आई. एन. एस. डब्ल्यू. ए. आर. ई. बी., सी. एस. वी. और अन्य राज्य स्तरीय संस्थान और लॉरी बेकर द्वारा किए गए कार्य।

प्र. 28. सभी के लिए आवास (एच. एफ. ए.) क्या है, इसके उद्देश्य और दायरा क्या है?

उत्तर। एच. एफ. ए. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एम. ओ. एच. यू. ए.) द्वारा मिशन मोड में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें 2022 तक सभी के लिए आवास के प्रावधान की परिकल्पना की गई है, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लेगा। मिशन का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी वासियों सहित शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं को निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा करना है: 1. संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी के साथ झुग्गी-झोपड़ी वासियों का पुनर्वास। ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास। लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी।

प्रश्न 29. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-2) क्या है?

उत्तर। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2 की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर, ओडिशा से 17.09.2024 पर योजना दिशानिर्देश जारी करके की है। पीएमएवाई-यू 2 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एम. आई. जी. श्रेणियों के एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सस्ती कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

प्र. 30. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-2) में हड़को की क्या भूमिका है?

उत्तर। पीएमएवाई (यू) के कार्यान्वयन में हड़को की भूमिका है: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/यू. एल. बी./पारस्ताताल और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को किफायती घरों के निर्माण के लिए राज्य और लाभार्थी हिस्से के लिए वित्तीय सहायता; निजी भागीदारी में किफायती आवास के तहत एजेंसियों को ऋण; डी. पी. आर. तैयार करने, सामाजिक प्रभाव अध्ययन आदि के लिए परामर्श; डी. पी. आर., निगरानी और संबंधित कार्यों की जांच; यू. एल. बी. अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण-प्रशिक्षण कार्यक्रम; भारत सरकार को दिशा देने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों में से एक के रूप में नामित

प्र. 31. क्या हडको कोई सीएसआर पहल या गतिविधि कर रहा है?

उत्तर। हां, हडको समय-समय पर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप एक औपचारिक संरचित सीएसआर नीति और जोर देने वाले क्षेत्रों की दिशा में महत्वपूर्ण आपदा पुनर्वास प्रयासों सहित विभिन्न सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, हडको ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत गतिविधियों के लिए अपने शुद्ध लाभ का एक हिस्सा निर्धारित करते हुए एक विशेष बजट बनाया है। इस विशेष बजट से सीएसआर के तहत गतिविधियों को हडको की विधिवत अनुमोदित सीएसआर नीति द्वारा विनियमित किया जाता है।

आर. टी. आई. पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. 32. सूचना क्या है?

उत्तर। सूचना किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है। इसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री शामिल हैं। इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी भी शामिल है जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी भी कानून के तहत प्राप्त किया जा सकता है।

प्र. 33. सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है?

उत्तर। "सार्वजनिक प्राधिकरण" संविधान द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित स्वशासन का कोई भी प्राधिकरण या निकाय या संस्था है। या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं, वे भी सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। सरकार द्वारा निकाय या गैर सरकारी संगठन का वित्तपोषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है।

प्र. 34. लोक सूचना अधिकारी क्या होता है?

उत्तर। सार्वजनिक प्राधिकरणों ने अपने कुछ अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया है। आर. टी. आई. अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को जानकारी देने के लिए वे जिम्मेदार हैं।

प्र. 35. सहायक लोक सूचना अधिकारी क्या होता है?

उत्तर। ये उप-मंडल स्तर के अधिकारी हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपना आर. टी. आई. आवेदन या अपील दे सकता है। ये अधिकारी आवेदन या अपील सार्वजनिक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी या संबंधित अपीलीय प्राधिकरण को भेजते हैं। एक सहायक लोक सूचना अधिकारी जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

विभिन्न डाकघरों में डाक विभाग द्वारा नियुक्त सहायक लोक सूचना अधिकारी भारत सरकार के तहत सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं।

प्र. 36. केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी लेने के लिए शुल्क क्या है?

उत्तर। एक व्यक्ति जो केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरण से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे आवेदन के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर का चेक या 10/- रुपये (दस रुपये) का भारतीय डाक आदेश भेजना होगा, जो सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय होगा। शुल्क का भुगतान नकद के माध्यम से लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को उचित रसीद के बदले में भी किया जा सकता है। हालाँकि, आर. टी. आई. शुल्क और भुगतान का तरीका भिन्न हो सकता है क्योंकि आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 की धारा 27 और धारा 28 के तहत उपयुक्त सरकार और सक्षम प्राधिकारी, क्रमशः, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाते हैं।

प्र. 37. बी. पी. एल. आवेदक के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क क्या है?

उत्तर। यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) श्रेणी का है, तो उसे कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उसे गरीबी रेखा से नीचे रहने के अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

प्र. 38. क्या आवेदन का कोई विशिष्ट प्रारूप है?

उत्तर। जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। हालांकि, आवेदन में आवेदक का नाम और पूरा डाक पता होना चाहिए।

प्र. 39. क्या जानकारी मांगने के लिए कोई कारण देना आवश्यक है?

उत्तर। सूचना चाहने वाले को जानकारी मांगने के लिए कारण देने की आवश्यकता नहीं है।

प्र. 40. क्या सूचना के प्रकटीकरण से छूट का कोई प्रावधान है?

उत्तर। अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 9 उन सूचनाओं के प्रकारों की गणना करती है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गई है। हालाँकि, धारा 8 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि उप-धारा 3 (1) के तहत छूट प्राप्त या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट प्राप्त जानकारी का खुलासा किया जा सकता है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को नुकसान से अधिक है।

प्र. 41. क्या आर. टी. आई. आवेदन दाखिल करने के लिए आवेदक को कोई सहायता उपलब्ध है?

उत्तर। यदि कोई व्यक्ति लिखित में अनुरोध करने में असमर्थ है, तो वह अपना आवेदन लिखने के लिए लोक सूचना अधिकारी की मदद ले सकता है और लोक सूचना अधिकारी को उसे उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए।

जहाँ किसी संवेदी रूप से विकलांग व्यक्ति को किसी दस्तावेज तक पहुँच देने का निर्णय लिया जाता है, वहाँ लोक सूचना अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी सहायता प्रदान करेगा जो निरीक्षण के लिए उपयुक्त हो।

प्र. 42. सूचना की आपूर्ति के लिए समय अवधि क्या है?

उत्तर। सामान्य तौर पर, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक आवेदक को जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि माँगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसे 48 घंटों के भीतर प्रदान किया जाएगा। यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से भेजा जाता है या इसे किसी गलत सार्वजनिक प्राधिकरण को भेजा जाता है, तो तीस दिन या 48 घंटे की अवधि में पांच दिन जोड़े जाएंगे, जैसा भी मामला हो।

प्र. 43. क्या आर. टी. आई. अधिनियम के तहत अपील का कोई प्रावधान है?

उत्तर। यदि किसी आवेदक को तीस दिनों या 48 घंटों के निर्धारित समय के भीतर जानकारी प्रदान नहीं की जाती है, या वह उसे दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो वह पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है जो लोक सूचना अधिकारी के रैंक में वरिष्ठ अधिकारी है। ऐसी अपील, उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन सूचना की आपूर्ति की 30 दिनों की सीमा समाप्त हो गई है या उस तारीख से जिस दिन लोक सूचना अधिकारी की जानकारी या निर्णय प्राप्त हुआ है। लोक प्राधिकारी का अपीलीय प्राधिकरण तीस दिनों की अवधि के भीतर या असाधारण मामलों में अपील प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

प्र. 44. क्या आर. टी. आई. अधिनियम के तहत दूसरी अपील की कोई गुंजाइश है?

उत्तर। यदि पहला अपीलीय प्राधिकरण निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश पारित करने में विफल रहता है या यदि अपीलकर्ता पहले अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील कर सकता है जिस दिन निर्णय पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए था या वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था।

प्र. 45. क्या इस अधिनियम के तहत शिकायतें की जा सकती हैं?

उत्तर। यदि हाँ, तो किन शर्तों के तहत? यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ है कि ऐसे अधिकारी को संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है; या सहायक लोक सूचना अधिकारी ने, जैसा भी मामला हो, लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित करने के लिए अपने आवेदन या अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है; या उसे आर. टी. आई. अधिनियम के तहत उसके द्वारा अनुरोध की गई किसी भी जानकारी तक पहुंच से इनकार कर दिया गया है; या उसे अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जानकारी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया गया है; या

उसे शुल्क की ऐसी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे वह अनुचित मानता है; या वह मानता है कि उसे अधूरी, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है, वह सूचना आयोग में शिकायत कर सकता है।

प्र. 46. थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन क्या है?

उत्तर। अधिनियम के संबंध में तीसरे पक्ष का अर्थ है नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जिसने जानकारी के लिए अनुरोध किया है। तीसरे पक्ष की परिभाषा में सार्वजनिक प्राधिकरण के अलावा एक सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है जिसे अनुरोध किया गया है।

प्र. 47. जानकारी प्राप्त करने का तरीका क्या है?

उत्तर। एक नागरिक जो अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखित रूप में आवेदन करना चाहिए जिसमें आवेदन किया गया है। आवेदन सटीक और विशिष्ट होना चाहिए। उसे शुल्क नियमों में निर्धारित आवेदन जमा करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

प्र. 48. क्या कोई संगठन आर. टी. आई. अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने से मुक्त है?

उत्तर। हां, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को छोड़कर जानकारी प्रदान करने से छूट दी गई है
